Dainik Jagran Edition Ranchi
17.3.2017 Page 2
Height 14.01cm Width 12.70 cm

'आधार' से रुका स्कूलों में ढाई लाख फर्जी नामांकन

नीरज अम्बष्ठ ● रांची

राज्य के प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या में लगभग ढाई लाख की कमी आ गई है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन ही कम हुआ। ऐसा सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की आधार सीडिंग (आधार नंबर से लिंक) करने से हुआ है। सरकारी स्कूलों के बच्चों की पहली बार आधार से लिंक करने से जहां डुप्लीकेसी कम हुई, वहीं फर्जी नामांकन पर रोक लगा।

यह खुलासा उस समय हुआ जब मिड डे मील योजना के बजट बनाने के क्रम में सभी जिलों से 2016-17 में हुए नामांकन की रिपोर्ट मांगी गई। इस वित्तीय वर्ष में 40 हजार प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में लगभग 48 लाख बच्चों का नामांकन हुआ। इससे ठीक पहले 2015-16 में कुल 50 लाख 42 हजार 957 विद्यार्थी (प्राइमरी-35,35,491, अपर प्राइमरी-15,07,466) नामांकित थे। इस तरह, बच्चों की संख्या में लगभग ढाई लाख की कमी आ गई। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक के अनुसार, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई विद्यार्थी एक से अधिक स्कूलों में नामांकन ले लेते थे। कुछ स्कूलों में फर्जी नामांकन भी दिखाया जाता था। सभी बच्चों को आधार से लिंक किए जाने से इसपर रोक लगी। उनके अनुसार, शत-प्रतिशत आधार सीडिंग होने से फर्जीवाड़े और डुप्लीकेसी में और भी कमी आएगी।

अच्छा प्रयास

50.5

लाख से घटकर 48 लाख हुई छात्र-छात्राओं की संख्या

राज्य सरकार सभी बच्चों की करा रही आधार सीडिंग

70 फीसद बच्चों की आधार सीडिंग

राज्य के चालीस हजार स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों में लगभग 90 फीसद बच्चों का आधार कार्ड बन गया है। वहीं, 70 फीसद बच्चों की आधार सीडिंग का कार्य पूरा हो गया है। 75 फीसद बच्चों का बैंक खाता भी खुल गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने तमाम योजनाओं को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत सारी राशि बच्चों के बैंक खाते में सीधे जा रही है। इससे भी फर्जी नामांकन पर रोक लगा है।

केंद्र ने की सराहना

10 मार्च को दिल्ली में मिड डे मील योजना की प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड की बैठक में आधार से लिंक किए जाने की सराहना हुई। इस बैठक में राज्य के स्कूलों में गठित बाल संसद तथा शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए गठित 'परिवर्तन दल' की भी सराहना हुई। केंद्र ने राज्य सरकार से 'परिवर्तन दल' का कान्सेप्ट नोट मांगा है ताकि इसे दूसरे राज्यों में भी लागू करने का निर्देश दिया जा सके।